मैसर्स ए. एस. मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

भारत संघ और अन्य

(सिविल अपील संख्या 1517/2013)

21 फरवरी 2013

[जस्टिस टी.एस. ठाकुर और ज्ञान सुधा मिश्रा]

अनुबंध - प्रतिवादी-प्राधिकरण द्वारा समाप्ति - समाप्ति को इस आधार पर चुनौती दी गई कि अपीलकर्ता को निष्पक्ष सुनवाई की आवश्यकता वाले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया - अनुबंध की समाप्ति अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले की गई थी और एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे सुनवाई प्रदान की गई - कारण बताओ नोटिस के साथ सभी प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न हैं। कारण बताओ नोटिस जारी करना और उस सामग्री का खुलासा करना जिसके आधार पर अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया गया था, के अनुपालन में था। अपीलकर्ता के प्रति निष्पक्षता की आवश्यकता - कार्रवाई करने वालों के खिलाफ दुर्भावना के किसी भी आरोप का अभाव और किसी भी पूर्वाग्रह का खुलासा करने में अपीलकर्ता की विफलता, सभी ने संकेत दिया कि प्रक्रिया निष्पक्ष थी और पर्याप्त रूप से,

यदि सख्त नहीं थी, तो आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया था। ऑडी अल्टरम पार्टेम - इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का काफी हद तक अनुपालन किया गया।

अनुबंध - राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क के विस्तार का उपयोग करने के लिए शुल्क के संग्रह के लिए - अपीलकर्ता को दिया गया - अनुबंध बाद में प्रतिवादी-प्राधिकरण द्वारा समाप्त कर दिया गया समाप्ति को इस आधार पर चुनौती दी गई कि प्रतिवादी-प्राधिकरण के पास यह मानने का कोई वास्तविक आधार नहीं था कि अपीलकर्ता ठेकेदार ने कोई अपराध किया था अनुबंध के नियमों और शर्तों का उल्लंघन इसकी समाप्ति की गारंटी देता है - माना गया: प्रतिवादी प्राधिकारी द्वारा नियोजित एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलकर्ता-ठेकेदार कदाचार में लिप्त था - यदि रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिस एजेंसी के खिलाफ अपीलकर्ता ने द्वेष या अन्य असंगत विचारों का कोई आरोप नहीं लगाया है, उसे स्वीकार कर लिया गया है, कोई कारण नहीं है कि वह प्रतिवादी को अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक सुरक्षित आधार प्रदान नहीं कर सका, खासकर जब वह एक ठेकेदार के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर रहा था, बड़े पैमाने पर जनता को अनावश्यक उत्पीड़न में डालना और उनसे कानूनी रूप से वसूली योग्य न होने वाले धन की मांग करना - अपीलकर्ता-ठेकेदार, इस प्रकार, किसी भी राहत का दावा करने का हकदार

नहीं है।

अनुबंध - प्रतिवादी-प्राधिकरण द्वारा समाप्ति - अपीलकर्ता ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शन सुरक्षा की जब्ती - का औचित्य - माना गया: उचित - ऐसी जब्ती अनुबंध की शर्तों और अनुबंध अधिनियम की धारा 74 के प्रावधानों के तहत प्रतिवादी-प्राधिकरण के लिए उपलब्ध थी सैमन ने मना नहीं किया - एक पीड़ित पक्ष उस पक्ष से मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है जिसने अनुबंध तोड़ा है, भले ही उल्लंघन के कारण वास्तविक क्षति या नुकसान साबित हुआ हो या नहीं - अनुबंध अधिनियम, 1872-धारा 72

अनुबंध - प्रतिवादी-प्राधिकरण द्वारा समाप्ति - अपीलकर्ता ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी का निरसन - औचित्य - माना गया: प्रतिवादी के रूप में उचित नहीं - प्राधिकरण ने पहले ही अपने द्वारा लगाया गया जुर्माना वसूल कर लिया था और प्रदर्शन सुरक्षा भी जब्त कर ली थी - हालांकि खंड 18 के संदर्भ में (बी) अनुबंध के अनुसार, प्रतिवादी-प्राधिकरण को अपीलकर्ता ठेकेदार द्वारा संग्रह की अधिकता का अनुमान लगाने और उससे इसकी वसूली करने का अधिकार था, हालांकि, रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि प्राधिकरण द्वारा ऐसा कोई अनुमान लगाया गया था और यदि ऐसा है तो आधार क्या है जिस पर ऐसा किया गया था - अपीलकर्ता-ठेकेदार द्वारा प्राप्त अतिरिक्त राशि के उचित अनुमान के बिना, यह प्रतिवादी-प्राधिकरण के लिए बैंक गारंटी को लागू करने के लिए खुला नहीं

था।

प्रशासनिक कानून - प्राकृतिक न्याय - के नियम - कठोर, अपरिवर्तनीय या सन्निहित नियम नहीं हैं - एक हद तक पहले के विचार से बदलाव आया है कि नियमों का तकनीकी उल्लंघन भी कार्रवाई को खराब करने के लिए पर्याप्त है।

प्रशासनिक कानून - प्राकृतिक न्याय - ऑडी अल्टरम पार्टम का सिद्धांत - आयोजित का उद्देश्य: मनमानी और निष्पक्ष खेल की चाहत पर प्रहार करना है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड (एनएचएआई) ने अपीलकर्ता को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के मुरैना-ग्वालियर खंड पर 42 किलोमीटर लंबी सड़क के उपयोग के लिए शुल्क वसूली का ठेका आवंटित किया था। पार्टियों के बीच संविदात्मक शर्तों का उल्लंघन किया गया। इसके परिणामस्वरूप सक्षम प्राधिकारी (प्रतिवादी) द्वारा संग्रहण अनुबंध समाप्त कर दिया गया।

व्यथित होकर अपीलकर्ता ने एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करते हुए प्रतिवादी-प्राधिकरण द्वारा जुर्माना लगाने और प्रदर्शन सुरक्षा को जब्त करने को बरकरार रखा, लेकिन बैंक गारंटी के निरसन को रद्द कर दिया।

तत्काल अपील में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि पार्टियों के बीच अनुबंध की समाप्ति कानूनी रूप से खराब थी, न केवल इसलिए कि अपीलकर्ता को निष्पक्ष सुनवाई की आवश्यकता वाले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन नहीं किया गया था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि प्रतिवादी के लिए कोई वास्तविक आधार नहीं था। -यह मानने का अधिकार कि अपीलकर्ता ने अनुबंध के नियमों और शर्तों का कोई उल्लंघन किया है, जिससे इसकी समाप्ति हो सकती है। प्रदर्शन सुरक्षा जब्त करने और बैंक गारंटी रद्द करने से संबंधित मुद्दा भी इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया

1.1 प्राकृतिक न्याय के नियम कठोर, अपरिवर्तनीय या सन्निहित नियम नहीं हैं जिन्हें स्ट्रेटजैकेट में डाला जा सकता है और न ही इन्हें इतना विकसित किया गया है कि सभी प्रकार के घरेलू न्यायाधिकरणों और जांचों पर सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सके। प्रत्येक मामले में जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है, अदालतें संक्षेप में यह देखती हैं कि क्या प्रभावित पक्ष को अपना मामला पेश करने के लिए उचित अवसर दिया गया था और क्या प्रशासनिक प्राधिकारी ने निष्पक्ष, निष्पक्ष और उचित रूप से कार्य किया था। इस प्रकार 'ऑडी अल्टरम पार्टम' के सिद्धांत का उद्देश्य मनमानी और निष्पक्ष

खेल की चाहत पर प्रहार करना है। प्राकृतिक न्याय के नियमों के उल्लंघन के आधार पर शिकायत की जांच करने वाली अदालत यह देखने का हकदार है कि क्या पीड़ित पक्ष को वास्तव में इस तरह के उल्लंघन के कारण कोई पूर्वाग्रह झेलना पड़ा है। उस हद तक पहले की सोच में बदलाव आया है कि नियमों का तकनीकी उल्लंघन भी कार्रवाई को ख़राब करने के लिए पर्याप्त है। [पैरा 8] [420-ए-सी, डी-ई]

1.2. मौजूदा मामले में, पार्टियों के बीच अनुबंध की समाप्ति अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनवाई प्रदान करने से पहले की गई थी। अपीलकर्ता को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में अपीलकर्ता के खिलाफ विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतें और अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपों की पुष्टि के लिए लगी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की एक प्रति सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न थे। अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका में कारण बताओ नोटिस को असफल रूप से चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए अपीलकर्ता को नोटिस का जवाब पेश करने का निर्देश दिया था. अपीलकर्ता तदनुसार प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुआ, अपना लिखित बयान प्रस्तुत किया और अपने मामले के समर्थन में सुना गया कि उसने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। जवाब में या सुनवाई में, अपीलकर्ता ने मामले से निपटने वाले अधिकारियों या तथ्यों को इकट्ठा

करने और सत्यापित करने के लिए उनके द्वारा नियोजित एजेंसी के खिलाफ किसी भी दुर्भावना, पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह का आरोप नहीं लगाया था। इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का काफी हद तक अनुपालन किया गया। यह तर्क कि अपीलकर्ता को उन व्यक्तियों से जिरह करने का अवसर दिया जाना चाहिए था जिनके बयान एजेंसी ने अपनी जांच और सत्यापन के दौरान दर्ज किए थे, जांच की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था। मुख्य रूप से अनुबंध के दायरे में, इसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या अपीलकर्ता ने पार्टियों के बीच अनुबंध संबंधी शर्तों का कोई उल्लंघन किया है। कारण बताओ नोटिस जारी करना और उस सामग्री का खुलासा करना जिसके आधार पर अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया गया था, अपीलकर्ता के प्रति निष्पक्षता की आवश्यकता के अनुपालन में था, जो प्रस्तावित समाप्ति से प्रभावित होने की संभावना थी। कार्रवाई करने वालों के खिलाफ दुर्भावना के किसी भी आरोप का अभाव और किसी भी पूर्वाग्रह का खुलासा करने में अपीलकर्ता की विफलता, सभी ने संकेत दिया कि प्रक्रिया निष्पक्ष थी और ऑडी अल्टरम पार्टेम की आवश्यकताओं के अनुपालन में सख्त नहीं तो पर्याप्त थी। [पैरा 15] [425-डी-एच; 426-ए-सी]

सुरेश कोशी जॉर्ज बनाम केरल विश्वविद्यालय एआईआर 1969

एससी 198: 1969 एससीआर 317: केशव मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1973) 1 एससीसी 380: 1973 (3) एससीआर 22; पी.डी. अग्रवाल बनाम भारतीय स्टेट बैंक (2006) 8 एससीसी 776: 2006 (1) पूरक। एससीआर 454; महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा बोर्ड बनाम के.एस. गांधी एवं अन्य (1991) 2 एससीसी 716: 1991 (1) एससीआर 772; महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बनाम परितोष भुपेशकुमार शेठ और अन्य। (1984) 4 एससीसी 27; भारत संघ बनाम मोहन लाल कपूर (1973) 2 एससीसी 836: 1974 (1) एससीआर 797; अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाम मंसूर अली खान (2000) 7 एससीसी 529: 2000 (2) सप्ल एससीआर 684 -पर भरोसा किया गया।

चरण लाल साहू बनाम भारत संघ (भोपाल गैस आपदा) (1990) 1 एससीसी 613: 1989 (2) सप्ल एससीआर 597 - संदर्भित।

रसेल बनाम ड्यूक ऑफ नॉरफ़ॉक 1949 1 सभी ईआर 109; रिज बनाम बाल्डविन (1963) 2 डब्ल्यू.एल.आर. 935-उल्लेखित।

प्रशासनिक कानून (सर विलम वेड), 9 वां संस्करण। पृ. 468-471-संदर्भित।

2.1. इसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं है, न ही उत्तरदाताओं के समक्ष

उपलब्ध सामग्री की सराहना में कोई विकृति है। प्रतिवादी-प्राधिकरण द्वारा नियोजित एजेंसी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट अपीलकर्ता के लिए हानिकारक है और स्पष्ट रूप से पता चला है कि अपीलकर्ता अनुबंध द्वारा कवर किए गए सड़क के विस्तार का उपयोग करने वाले वाहनों के मालिकों, ड्राइवरों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने जैसे कदाचार में लिप्त थे। यदि उस एजेंसी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट, जिसके खिलाफ अपीलकर्ता पर द्वेष या अन्य असंगत विचारों का कोई आरोप नहीं है, स्वीकार कर ली जाती है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि वह प्रतिवादी को कार्रवाई करने के लिए एक सुरक्षित आधार प्रदान नहीं कर सके, खासकर जब अपीलकर्ता दुर्व्यवहार कर रहा हो। एक ठेकेदार के रूप में इसकी स्थिति, बड़े पैमाने पर जनता को अनावश्यक उत्पीड़न और उनसे कानूनी रूप से वसूली योग्य न होने वाले धन की वसूली में डाल रही है। एकत्र की गई सामग्री को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुबंध की समाप्ति के लिए सही आधार बनाया जा सकता है और बनाया गया है। (पैरा 19] [428-बी-एफ]

2.2. अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के असाधारण रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किसी भी राहत का दावा करने का हकदार नहीं था। उच्च न्यायालय अपीलकर्ता को सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष उचित नागरिक कार्रवाई में निवारण की मांग कर सकता था, चाहे वह नुकसान के लिए हो या प्रतिवादी द्वारा जब्त की गई राशि की वसूली के लिए हो। हाई

कोर्ट ने ऐसा नहीं किया है. इसने अपीलकर्ता को इस हद तक आंशिक राहत दी है कि प्रदर्शन सुरक्षा की जब्ती और जुर्माने की राशि के मद्देनजर बैंक गारंटी का आह्वान उचित नहीं था। किसी भी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है, जो प्रकृति में असाधारण और विवेकाधीन दोनों है। [पैरा 20] [428-एफ-एच; 429-ए-बी]

2.3. अपीलकर्ता ने अनुबंध का उल्लंघन किया था शर्तों के तहत, निर्दोष नागरिकों को कानून द्वारा अपेक्षित राशि से अधिक भुगतान करने के लिए परेशान किया गया और इस प्रकार न्यायसंगत विचारों पर उच्च न्यायालय के असाधारण रिट क्षेत्राधिकार में राहत का दावा करने के लिए अदालत में जाने से पहले खुद को अवांछनीय रूप से समृद्ध किया गया। इस तरह के प्रयास को उच्च न्यायालय द्वारा विफल किया जाना चाहिए था, जैसा कि वास्तव में किया गया है, चाहे आंशिक रूप से ही क्यों न हो। [पैरा 21] [430-बी-सी]

हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड चौथा संस्करण खंड-16, पीपी 874-876 - संदर्भित।

3. उच्च न्यायालय ने माना है कि 2,41,097/- रुपये के जुर्माने के अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत बैंक ड्राफ्ट

में से 2,20,00,125/- रुपये की राशि पहले ही वसूल कर ली थी। प्रदर्शन सुरक्षा की ओर; इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कुल राशि अनुबंध के तहत उसे देय राशि से अधिक थी यदि अनुबंध अवधि के अंत तक इसे परिश्रमपूर्वक निष्पादित किया गया था और किसी भी अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए बैंक गारंटी का आह्वान अनुचित था। फैसले के उस हिस्से के खिलाफ प्राधिकरण द्वारा कोई अपील नहीं की गई है, हालांकि प्राधिकरण की ओर से यह तर्क दिया गया था कि अनुबंध के खंड 18 (बी) के संदर्भ में, प्राधिकरण को अपीलकर्ता द्वारा संग्रह की अधिकता का अनुमान लगाने का अधिकार था। ठेकेदार और उससे इसकी वसूली करो। हालाँकि, रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्या प्राधिकरण द्वारा ऐसा कोई अनुमान लगाया गया था और यदि हाँ तो वह किस आधार पर किया गया था। अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त अतिरिक्त राशि के उचित अनुमान के बिना, प्रतिवादी के लिए बैंक गारंटी का उपयोग करना और उसके अंतर्गत कवर की गई 2,20,00,125/- रुपये की पूरी राशि की वसूली करना संभव नहीं था। उस दृष्टिकोण से, उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि बैंक गारंटी का आह्वान उचित नहीं था। [पैरा 22,24] [430-डी-एफ; 431-एफ-जी, एच; 432-ए-बी]

4. जहां तक अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत बैंक ड्राफ्ट से 2,20,00,125/- रुपये की प्रदर्शन सुरक्षा की वसूली का सवाल है, ऐसी जब्ती अनुबंध की शर्तों के तहत प्रतिवादी-प्राधिकरण के लिए उपलब्ध थी

और अनुबंध अधिनियम की धारा 74 के प्रावधान इस पर रोक नहीं लगाते हैं। एक पीड़ित पक्ष उस पक्ष से मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है जिसने अनुबंध तोड़ा है, चाहे उल्लंघन के कारण वास्तविक क्षति या नुकसान साबित हुआ हो या नहीं और न्यायालय के पास, निर्धारित दंड की बाहरी सीमा के अधीन, अधिकार क्षेत्र है। मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा मुआवजा दें जो वह उचित समझे। यह अनिवार्य रूप से कानून और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न होगा जिसे रिट कोर्ट संभवतः तय नहीं कर सकता है। यदि अपीलकर्ता ने संविदात्मक शर्तों के संदर्भ में अपीलकर्ता द्वारा वसूली योग्य राशि की तर्कसंगतता पर सवाल उठाया है, तो अपीलकर्ता को उचित नागरिक कार्रवाई में इसके समाधान की मांग करनी चाहिए थी। [पैरा 25] [432-सी-डी, ई-जी]

फ़तेह चंद बनाम बालकिशन दास एएलआर 1963 एससी 1405: 1964 एससीआर 515; यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राम आयरन फाउंड्री (1974) 2 एससीसी 231: 1974 (3) एससीआर 556 और सेल बनाम गुप्ता ब्रदर स्टील ट्यूब्स (2009) 10 एससीसी 63 -पर भरोसा किया गया।

केस कानून संदर्भ:

1969 एससीआर 317	पर भरोसा	पैरा 9
1949 1 सभी आईएस 109	संदर्भित किया	पैरा 9

1973 (3) एससीआर 22	पर भरोसा	पैरा 10
(1963) 2 डब्ल्यू.एल.आर. 935	संदर्भित	पैरा 10
2006 (1) सप्ल एससीआर 454	भरोसा किया	पैरा 11
1989 (2) सप्ल एससीआर 597	संदर्भित	पैरा 11
1991 (1) एससीआर 772	भरोसा किया	पैरा 12
(1984) 4 एससीसी 27	भरोसा किया	पैरा 13
1974 (1) एससीआर 797	भरोसा किया	पैरा 13
2000 (2) सप्ल एससीआर 684	भरोसा किया	पैरा 14
1964 एससीआर 515	भरोसा किया	पैरा 25
1974 (3) एससीआर 556	भरोसा किया	पैरा 25
(2009) 10 एससीसी 63	भरोसा किया	पैरा 25

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1517/ 2013

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, खंडपीठ, ग्वालियर रिट अपील संख्या 491/ 2007 में के निर्णय और आदेश दिनांक 08.08.2007 से।

अपीलार्थी की ओर से ए.के. चितले, नीरज शर्मा, सुमित कुमार

शर्मा।

गुरब बनर्जी, एएसजी, प्रवीण जैन, तनुप्रिया, हसीब (एम.वी. किनी और सहयोगियों के लिए) उत्तरदाताओं के लिए.

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति स्वीकृत।

2. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की खंडपीठ द्वारा पारित 8 अगस्त, 2007 के एक आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर 2007 की रिट अपील संख्या 491 को खारिज कर दिया गया है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 2007 की रिट याचिका संख्या 720 को खारिज करते हुए पारित किया गया। रिट याचिका संख्या 720/2007 में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में पक्षों के बीच मुकदमेबाजी के कई दौरों को उचित रूप से दोहराया गया है और उसी के खिलाफ दायर रिट अपील को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा ताज़ा किया गया है। इस दृष्टि से यह हमारे लिए अनावश्यक है कि हम उस संपूर्ण तथ्यात्मक पृष्ठभूमि का वर्णन करें जिसमें इस अपील में विवाद उत्पन्न हुआ है, सिवाय कि इस अपील के निपटान के लिए ऐसा करना हमारे लिए बिल्कुल आवश्यक है।

3. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड (संक्षेप में एनएचएआई) ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 के मुरैना-ग्वालियर खंड पर 61.00 से किमी.103 तक के राष्ट्रीय राजमार्गों के उपयोग के लिए शुल्क के संग्रह के लिए एक अनुबंध देने के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं।अन्य लोगों के बीच अपीलकर्ता ने भी एक प्रस्ताव दिया, जिसे एनएचएआई ने 14 मार्च, 2006 के अपने पत्र के अनुसार स्वीकार कर लिया, जिसमें अपीलकर्ता को सुरक्षा 2,20,00,125/- रुपये की राशि का डिमांड ड्राफ्ट और समान राशि एक बैंक के लिए कहा गया था जो अनुबंध में निहित नियमों और शर्तों के उचित पालन के लिए 15 महीने की अवधि के लिए वैध होगी। इन दोनों आवश्यकताओं को अपीलकर्ता द्वारा संतुष्ट किया गया जिसके परिणामस्वरूप 1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक शुरू होने वाले उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह का अनुबंध अंततः उसके पक्ष में आवंटित किया गया। इसमें कोई विवाद नहीं है कि उक्त आवंटन के अनुसार अपीलकर्ता ने समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार निर्धारित शुल्क एकत्र करना शुरू कर दिया और उसी के तहत निर्धारित मासिक किश्तें भी जमा करना शुरू कर दिया।

4. एनएचएआई द्वारा समय-समय पर कुछ उल्लंघनों पर ध्यान दिया गया, जिसमें इस आशय की शिकायतें भी शामिल थीं कि अपीलकर्ता टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों से अतिरिक्त शुल्क वसूल रहा था। इसके

परिणामस्वरूप 27 जुलाई, 2006 के एक पत्र के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा संग्रह अनुबंध को समाप्त कर दिया गया और 2,20,00,125/- रुपये की सुरक्षा जब्त कर ली गई। प्रतिवादी द्वारा समाप्ति के आदेश से दोनों पक्षों के बीच मुकदमेबाजी शुरू हो गई, जिसमें उच्च न्यायालय के समक्ष कई दौर चले। हम उन कार्यवाहियों की प्रकृति और समय-समय पर पारित आदेशों से तत्काल विचार नहीं करते है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुबंध की समाप्ति को एक बार उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश 25 जनवरी, 2007 के अपने आदेश में के अनुपालन में अपीलकर्ता को बताओ नोटिस और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद इसे दूसरी बार समाप्त कर दिया गया था।

5. अनुबंध की नए सिरे से समाप्ति और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जब्ती के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष 2007 की रिट याचिका संख्या 720 दायर की।18 जून, 2007 के अपने आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने उक्त याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और जुर्माना लगाने और निष्पादन गारंटी को जब्त करने के आदेश को बरकरार रखते हुए, प्रतिवादी द्वारा बैंक गारंटी को रद्द करने को अनुचित करार इस आधार पर किया गया। इस तथ्य के संबंध में कि प्रतिवादी को पहले ही संग्रहण शुल्क के रूप में 7,33,33,750/- रुपये, निष्पादन सुरक्षा की जब्ती के लिए

2,20,00,125/- रुपये और 2,41,097/- रुपये की जुर्माना राशि प्राप्त हो चुकी है जो कुल मिलाकर 9,55,74,970/- रुपये है, जो कि प्रतिवादी को भुगतान की जाने वाली अनुबंधित राशि 8,80,00,500/- रुपये से अधिक थी। उच्च न्यायालय ने माना कि अनुबंध की समाप्ति और अपीलकर्ता द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए निष्पादन सुरक्षा की जब्ती, प्रतिवादी द्वारा अधिक शुल्क वसूलने और अपीलकर्ता द्वारा किया गया अन्य उल्लंघन के संबंध में सामग्री एकत्र करने के लिए तैनात एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आलोक में पूरी तरह से उचित थी।

6. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से व्यथित महसूस करते हुए अपीलकर्ता ने रिट अपील संख्या 491/2007 प्रस्तुत की, जिसे उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 8 अगस्त, 2007 के अपने आदेश द्वारा सुना और खारिज कर दिया। वर्तमान अपील उक्त आदेश की सत्यता पर सवाल उठाती है।

7. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को काफी हद तक सुना है, जिन्होंने हमें समय-समय पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों सहित रिकॉर्ड के बारे में बताया है।

8. अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि पक्षकारों के बीच अनुबंध की समाप्ति कानूनी रूप अनुचित से थी, न केवल इसलिए कि अपीलकर्ता को निष्पक्ष सुनवाई की आवश्यकता वाले प्राकृतिक न्याय के

सिद्धांतों का अनुपालन नहीं किया गया था, बल्कि इसलिए भी कि प्रतिवादी-प्राधिकरण को यह मानने का कोई वास्तविक आधार नहीं था कि अपीलकर्ता ने अनुबंध के नियमों और शर्तों का कोई उल्लंघन किया है जिससे इसकी समाप्ति की आवश्यकता है। हम किसी भी तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। कारण दूर-दूर तक नजर नहीं आते प्राकृतिक न्याय के नियम, जो अब तक काफी अच्छी तरह से स्थापित हो चुके हैं, कठोर, अपरिवर्तनीय या सन्निहित नियम नहीं हैं जिन्हें स्ट्रेटजैकेट में डाला जा सके और न ही इन्हें इतना विकसित किया गया है कि सभी प्रकार के घरेलू न्यायाधिकरणों और जांचों पर सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सके। प्रत्येक मामले में जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है, अदालतें संक्षेप में यह देखती हैं कि क्या प्रभावित पक्ष को अपना मामला पेश करने के लिए उचित अवसर दिया गया था और क्या प्रशासनिक प्राधिकारी ने, निष्पक्ष और उचित रूप से कार्य किया था। इस प्रकार ऑडी अल्टरम पार्टम के सिद्धांत का उद्देश्य मनमानियों पर प्रहार करना है और निष्पक्ष व्यवहार की अपेक्षा है। इसलिए, इस विषय पर न्यायिक घोषणाओं ने माना है कि प्राकृतिक न्याय की मांग अलग-अलग स्थितियों में भिन्न हो सकती हैं, जो न केवल प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं, बल्कि ट्रिब्यूनल की शक्तियों और संरचना और उन नियमों और विनियमों पर भी निर्भर करती हैं। जिसके अधीन यह कार्य करता है प्राकृतिक न्याय के नियमों के उल्लंघन के आधार पर

शिकायत की जांच करने वाली अदालत यह देखने का हकदार है कि क्या पीड़ित पक्ष को वास्तव में इस तरह के उल्लंघन के कारण कोई पूर्वाग्रह झेलना पड़ा है। उस हद तक पहले की सोच में बदलाव आया है कि नियमों का तकनीकी उल्लंघन भी कार्रवाई को ख़राब करने के लिए पर्याप्त है।इस विषय पर काफी न्यायिक घोषणाएँ हैं। हम इस विषय पर केवल कुछ निर्णयों का ही उल्लेख कर सकते हैं जो हमारी राय में पर्याप्त होने चाहिए।

9. सुरेश कोशी जॉर्ज बनाम केरल विश्वविद्यालय, एआईआर 1969 एससी 198 में, इस न्यायालय ने नियमों की सामग्री और व्यापकता की जांच करते हुए रसेल बनाम ड्यूक ऑफ नोरफोक, [1949] 1 ऑल ईआर 109 में व्यक्त दृष्टिकोण को इन शब्दों में मंजूरी दे दी। :

> "7... ... नैसर्गिक न्याय के नियम मूर्त नियम नहीं हैं। यह प्रश्न कि क्या किसी दिए गए मामले में अपनाई गई प्रक्रिया से प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताएं पूरी हुई हैं, काफी हद तक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, ट्रिब्यूनल के संविधान और उन नियमों पर निर्भर होना चाहिए जिनके तहत यह कार्य करता है।
>
> 8. रसेल बनाम ड्यूक ऑफ नॉरफ़ॉक में, [1949] 1 सभी ईआर 109 पृष्ठ 118 पर, टकर, एलजे यह देखा:

"मेरे विचार से, ऐसे कोई शब्द नहीं हैं जो हर तरह की जांच और हर तरह के घरेलू न्यायाधिकरण के लिए सार्वभौमिक अनुप्रयोग के हों। प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताएं मामले की परिस्थितियों, जांच की प्रकृति, उन नियमों पर निर्भर होनी चाहिए जिनके तहत ट्रिब्यूनल कार्य कर रहा है, जिस विषय वस्तु से निपटा जा रहा है, इत्यादि। तदनुसार, मुझे समय-समय पर उपयोग की जाने वाली प्राकृतिक न्याय की परिभाषाओं से अधिक सहायता नहीं मिलती है, लेकिन, जो भी मानक अपनाया जाता है, एक आवश्यक बात यह है कि संबंधित व्यक्ति को अपना मामला पेश करने का उचित अवसर मिलना चाहिए।"

10. केशव मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ, (1973) 1 एससीसी 380 में इस न्यायालय ने रिज बनाम बाल्डविन, (1963) 2 डब्लूएलआर 935 में लॉर्ड रीड की टिप्पणियों को मंजूरी दी और कहा:

"8... ... हमें नहीं लगता कि इस तरीके से कोई निश्चित या कठोर मानदंड निर्धारित करना उचित या वांछनीय है। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा को सीधे-सीधे दायरे में नहीं रखा जा सकता। इसलिए, विभिन्न निर्णयों से प्राकृतिक न्याय की परिभाषाओं या मानकों की तलाश करना और

फिर उन्हें किसी भी मामले के तथ्यों पर लागू करने का प्रयास करना व्यर्थ है। एकमात्र आवश्यक बिंदु जिसे सभी मामलों में ध्यान में रखा जाना चाहिए वह यह है कि संबंधित व्यक्ति को अपना मामला पेश करने का उचित अवसर मिलना चाहिए और संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी को , निष्पक्ष और तर्कसंगत रूप से कार्य करना चाहिए। जहाँ तक प्रशासनिक अधिकारियों का सवाल है, उनका कर्तव्य न्यायिक रूप से कार्य करना इतना नहीं है जितना कि निष्पक्षता से कार्य करना है। उदाहरण के लिए, इनके (एक शिशु), (1967) 2 क्यूबी 617 में लॉर्ड पार्कर की टिप्पणियाँ देखें। इसका मतलब केवल यह है कि प्राकृतिक न्याय के ऐसे उपाय लागू किए जाने चाहिए जैसा कि रिज बनाम बाल्डविन मामले में लॉर्ड रीड द्वारा वर्णित किया गया था। (उपरोक्त) को "सटीक परिभाषा के प्रति असंवेदनशील, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति विशेष परिस्थितियों में एक उचित प्रक्रिया के रूप में क्या मानेगा"। हालाँकि, निष्पक्ष-व्यवहार की अवधारणा के अनुप्रयोग के लिए भी वास्तविक लचीलेपन की आवश्यकता होती है। सब कुछ किसी मामले के वास्तविक तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जैसा कि टकर, एलजे ने रसेल बनाम ड्यूक ऑफ नोरफोक

में देखा, [1949] 1 एआइआर 109:

"प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताएं मामले की परिस्थितियों, जांच की प्रकृति ऽन नियमों पर निर्भर होनी चाहिए जिनके तहत न्यायाधिकरण कार्य कर रहा है, जिस विषय-वस्तु से निपटा जा रहा है इत्यादि।"

11. पीडी अग्रवाल बनाम भारतीय स्टेट बैंक, (2006) 8 एससीसी 776 का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जहां इस न्यायालय ने चरण लाल साहू बनाम भारत संघ, (भोपाल गैस आपदा) (1990) 1 एससीसी 613 में मुखर्जी, जे. द्वारा की गई टिप्पणियों को निम्नलिखित शब्दों में मंजूरी दी थी।) , :

"30. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को एक स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूले में नहीं रखा जा सकता। इसे परिस्थितिजन्य लचीलेपन में देखा जाना चाहिए। इसके अलग पहलू हैं. हाल के समय में इसमें भी व्यापक बदलाव आया है।

31. अजीत कुमार नाग बनाम जीएम (पीजे), इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (2005) 7 एससीसी 764, में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीश पीठ ने राय दी: (एससीसी पीपी.785-86, पैरा 44)

"44. हम सामान्य नियम से अवगत हैं कि किसी व्यक्ति की निष्पक्ष सुनवाई और निष्पक्ष अपील होनी चाहिए और उसे अनुचित सुनवाई और निष्पक्ष अपील से संतुष्ट होने के लिए नहीं कहा जा सकता है। हम इस सामान्य सिद्धांत के प्रति भी सचेत हैं कि फैसले से पहले की सुनवाई बेहतर होती है और "हमेशा फैसले के बाद की सुनवाई पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हम आगे जानते हैं कि यह कहा गया है कि व्यक्तियों के कानूनों के अलावा, भगवान के कानून भी ऑडी अल्टरम पार्टम के नियम का पालन करते हैं। ऐसा कहा गया है कि मानव इतिहास में पहली सुनवाई ईडन गार्डन में दी गई थी। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को यह कारण बताने का अवसर देने से पहले सज़ा नहीं दी कि उन्होंने निषिद्ध फल क्यों खाया था। (देखें आर. बनाम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय [1723] 1 स्ट्रेट 557) लेकिन हम यह भी जानते हैं कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत कठोर या अपरिवर्तनीय नहीं हैं और इसलिए उन्हें किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। उन्हें परिस्थितियों की तात्कालिकता के अनुरूप झुकना होगा और बदलना होगा। उन्हें उनकी सीमा के भीतर ही सीमित रखा जाना चाहिए और उन्हें जंगली ढंग से घूमने की अनुमति नहीं दी जा

सकती। यह कहा गया है: "आखिरकार 'एक बड़ा सही काम करने के लिए', कभी-कभी 'थोड़ा गलत करने' की भी अनुमति है।" [चरण लाल साहू बनाम भारत संघ, (भोपाल गैस आपदा) (1990) 1 एससीसी 613, 705, पैरा 124 में श्री मुखर्जी, मुख्य न्यायाधीश कानूनी प्रावधानों की व्याख्या करते समय, अदालत जीवन की कठोर वास्तविकताओं से अनजान नहीं हो सकती। हमारी राय में, ऐसे मामलों से निपटने में अदालत का दृष्टिकोण पांडित्यपूर्ण के बजाय व्यावहारिक, सिद्धांतवादी के बजाय यथार्थवादी, औपचारिक के बजाय कार्यात्मक और 'अभूतपूर्व' के बजाय व्यावहारिक होना चाहिए।

xxx xxx

xxx xxx

39. एसएल जगमोहन, (1980) 4 एससीसी 379 में इस न्यायालय का निर्णय, जिसमें श्री राव ने यह तर्क दिया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन न करना पूर्वाग्रह का कारण बनता है या इसे नहीं पढ़ा जाना चाहिए "क्योंकि यह पूर्वाग्रह का कठिनाई का कारण बनता है"", को वर्तमान मामले में लागू नहीं कहा जा सकता। जैसा कि यहां पहले

देखा गया है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में व्यापक बदलाव आया है। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम एसके शर्मा, (1996) 3 एससीसी 364 औ राजेंद्र सिंह बनाम एमपी राज्य, (1996) 5 एससीसी 460 में इस न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए कानून का सिद्धांत यह है कि शिकायतकर्ता को कुछ वास्तविक पूर्वाग्रह अवश्य होने चाहिए .न्यायालय अपनी पहले की अवधारणा से हट गया है कि एक छोटे से उल्लंघन के परिणामस्वरूप भी आदेश रद्द कर दिया जाएगा। ऑडी अल्टरम पार्टम के सिद्धांत में, उन मामलों के बीच स्पष्ट अंतर रखा गया है जहां बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हुई थी और उन मामलों में जहां सिद्धांत का केवल तकनीकी उल्लंघन था। न्यायालय प्रत्येक मामले में प्राप्त तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करता है। इसे मामले के प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ के बिना कारण के लागू नहीं किया जाता है। यह कोई अनियंत्रित घोड़ा नहीं है. इसे स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूले में नहीं डाला जा सकता. (विवेका नंद सेठी बनाम चेयरमैन, जेएंडके बैंक लिमिटेड देखें । (2005) 5 एससीसी 337 और स्टेट ऑफ यूपी बनाम नीरज अवस्थी (2006) 1 एससीसी 667। मोहम्मद

सरताज बनाम स्टेट ऑफ यूपी (2006) 2 एससीसी 315) भी देखें (जोर दिया गया)''

12. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा बोर्ड में वि. केएस गांधी और अन्य, (1991) 2 एससीसी 716, में इस न्यायालय ने कानूनी स्थिति को दोहराते हुए कहा:

> "22...प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता (एसआईसी) निष्पक्ष खेल के स्पष्ट उल्लंघन में मनमाने निर्णय पर पहुंचने के लिए निवारक के रूप में कार्य करती है। लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की प्रयोज्यता कानून के एक अमूर्त प्रस्ताव के रूप में अचूक नियम या स्ट्रेट-जैकेट फॉर्मूला नहीं है। यह मामले के तथ्यों, जांच की प्रकृति और व्यक्ति के अधिकारों और संबंधित परिस्थितियों पर आदेश/निर्णय के प्रभाव पर निर्भर करता है।"

13. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बनाम वी. परितोष भुपेशकुमार शेठ और अन्य।(1984) 4 एससीसी 27, इस न्यायालय ने भारत संघ बनाम मोहन लाल कपूर, (1973) 2 एससीसी 836 में मैथ्यू, जे. द्वारा की गई टिप्पणियों को दोहराया कि ऑडी अल्टर्राम पार्टेम नियम मात्र अपेक्षाओं के गोधूलि क्षेत्र में शामिल प्राकृतिक न्याय के क्षितिज का विस्तार करना समीचीन नहीं था, चाहे वे कितनी भी

महान क्यों न हों।

14. हम अंततः इस न्यायालय के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम मंसूर अली खान, (2000) 7 एससीसी 529 के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं, जहां इस न्यायालय ने अनुमोदन के साथ सर विलम वेड (प्रशासनिक कानून, 9 वां संस्करण पीपी) की निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत किया था। 468-471)

> "... इसके बारे में कठोर नियम बनाना संभव नहीं है, की प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कब लागू करना है, ना ही उनके दायरे और सीमा के बारे में.. शिकायतकर्ता के प्रति कुछ वास्तविक पूर्वाग्रह भी रहे होंगे; प्राकृतिक न्याय के केवल तकनीकी उल्लंघन जैसी कोई चीज़ नहीं है। प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताएं मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, जांच की प्रकृति, उन नियमों पर निर्भर होनी चाहिए जिनके तहत न्यायाधिकरण कार्य कर रहा है, जिस विषय-वस्तु से निपटा जाना है इत्यादि।"

15. मामले पर विचार करते हुए हम पाते हैं कि पार्टियों के बीच अनुबंध की समाप्ति अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनवाई प्रदान करने से पहले की गई थी। 24 नवंबर, 2006 को अपीलकर्ता को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में

अपीलकर्ता के खिलाफ विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतें और अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपों की पुष्टि के लिए लगी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की एक प्रति सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न थे। अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2006 की रिट याचिका संख्या 6338 में कारण बताओ नोटिस को असफल रूप से चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए अपीलकर्ता को नोटिस का जवाब पेश करने का निर्देश दिया था. अपीलकर्ता तदनुसार 12 जनवरी, 2007 को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुआ, अपना लिखित बयान प्रस्तुत किया और अपने मामले के समर्थन में सुना गया कि उसने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। जवाब में या सुनवाई में, अपीलकर्ता ने मामले से निपटने वाले अधिकारियों या तथ्यों को इकट्ठा करने और सत्यापित करने के लिए उनके द्वारा नियोजित एजेंसी के खिलाफ किसी भी दुर्भावना, या पूर्वाग्रह का आरोप नहीं लगाया था। इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का काफी हद तक पालन किया गया। यह तर्क कि अपीलकर्ता को उन व्यक्तियों से जिरह करने का अवसर दिया जाना चाहिए था जिनके बयान एजेंसी ने अपनी जांच और सत्यापन के दौरान दर्ज किए थे, जांच की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था। मुख्य रूप से अनुबंध के दायरे में, इसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या अपीलकर्ता ने पार्टियों के बीच अनुबंध संबंधी शर्तों का कोई उल्लंघन किया है। कारण बताओ नोटिस जारी करना और उस सामग्री का खुलासा

करना जिसके आधार पर अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया गया था, अपीलकर्ता के प्रति निष्पक्षता की आवश्यकता के अनुपालन में था, जो प्रस्तावित समाप्ति से प्रभावित होने की संभावना थी। कार्रवाई करने वालों के खिलाफ दुर्भावना के किसी भी आरोप का अभाव और किसी भी पूर्वाग्रह का खुलासा करने में अपीलकर्ता की विफलता, सभी ने संकेत दिया कि प्रक्रिया निष्पक्ष थी और ऑडी अल्टरम पार्टेम की आवश्यकताओं के अनुपालन में सख्त नहीं तो पर्याप्त थी। इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा दी गई चुनौती का पहला चरण विफल हो गया है और इसे खारिज कर दिया गया है।

16. अब इस प्रश्न पर आते हैं कि क्या प्रतिवादी-प्राधिकरण के पास अनुबंध की समाप्ति को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। उच्च न्यायालय ने साक्ष्य एकत्र करने और आरोपों के सत्यापन के लिए तैनात एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का विस्तार से उल्लेख किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रतिवादी ने की वर्तमान मामले में अपीलकर्ता द्वारा किए जा रहे कथित कदाचार के संबंध में जानकारी और साक्ष्य का संग्रह के समाबन्धन में अपनाई गई विधि और प्रक्रिया को पूरी तरह से उचित ठहराया था।। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने इस पहलू पर विचार करते हुए कहा:

"विवेकपूर्ण जांच करने वाली एजेंसी के किसी भी सदस्य के

खिलाफ दुर्भावना, या व्यक्तिगत पूर्वाग्रह का कोई आरोप नहीं है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मेरा मानना है कि याचिकाकर्ता द्वारा की जा रही अवैधताओं का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अपनाया गया तरीका एक उचित तरीका है और इससे याचिकाकर्ता पर कोई पूर्वाग्रह या पक्षपात नहीं हुआ है। रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर संलग्न आर/7 में निहित एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को इस न्यायालय द्वारा खारिज किया जा सके, इस रिपोर्ट को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि इसे याचिकाकर्ता में पीठ पीछे एकत्र किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा की गई अनियमितता की प्रकृति का पता केवल तभी लगाया जा सकता है जब उत्तरदाताओं द्वारा की गई विवेकपूर्ण जांच में इस तरह से कार्य किया गया हो जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हो। प्रस्तुत रिपोर्ट याचिकाकर्ता के समक्ष रखी गई, उन्हें लिखित और व्यक्तिगत रूप से अपना बचाव और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। रिकॉर्ड्स ने संकेत दिया कि याचिकाकर्ता यह दिखाने के लिए कोई ठोस सामग्री पेश करने में असमर्थ था कि यह रिपोर्ट उचित नहीं है और इस पर भरोसा नहीं किया जा

सकता है।''

17. उपरोक्त आदेश के विरुद्ध दायर अपील में, अपीलकर्ता ने एकल न्यायाधीश द्वारा निम्नलिखित शब्दों में तैयार किए गए केवल प्रश्न संख्या (III) और (V) में शामिल दो पहलुओं के संबंध में शिकायत की थी।: (III) क्या अनुबंध को समाप्त करने की कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई है और क्या अनुबंध को रद्द करना याचिकाकर्ता द्वारा किए गए उल्लंघन के सबूत पर आधारित है?(V) क्या संविदा अधिनियम की धारा 74 का प्रावधान वर्तमान मामले में लागू होता है और निष्पादन सुरक्षा को जब्त करना और बैंक गारंटी को रद्द करना इस न्यायालय द्वारा मनमाना और अनुचित हस्तक्षेप है?

18. उपरोक्त प्रश्न संख्या III से निपटते समय, डिवीजन बेंच ने कहा:

> "मुद्दा संख्या III के संबंध में, विद्वान रिट कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लाए गए विभिन्न तथ्यों पर भरोसा करते हुए पैराग्राफ 21 में एक स्पष्ट निष्कर्ष दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा सड़क से अधिक दर वसूलने का जो तरीका अपनाया गया, वह अनुबंध का स्पष्ट उल्लंघन था और इसके तहत अनुबंध समझौते के खंड 18 (ए) के अनुसार, यह निर्धारित किया गया था, और इसमें निर्धारित उल्लंघन के लिए जुर्माना

लगाने और वसूलने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भी अधिकार दिया गया था। हमारी सुविचारित राय में रिट कोर्ट ने उपरोक्त निष्कर्ष को दर्ज करने में कोई गलती नहीं की।"

19. हमारी राय में, कानून की कोई त्रुटि नहीं है, न ही उत्तरदाताओं के समक्ष उपलब्ध सामग्री की विवेचना में कोई विकृति है। प्रतिवादी-प्राधिकरण द्वारा नियोजित एजेंसी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट अपीलकर्ता के लिए हानिकारक थी और स्पष्ट रूप से पता चला कि अपीलकर्ता अनुबंध द्वारा कवर की गई सड़क के विस्तार का उपयोग करने वाले वाहनों के मालिकों / चालकों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने जैसे कदाचार में लिप्त था। हमें विपरीत दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए विशेष रूप से कुछ भी नहीं बताया गया है। यदि उस एजेंसी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट, जिसके खिलाफ अपीलकर्ता पर द्वेष या अन्य असंगत विचारों का कोई आरोप नहीं है, स्वीकार कर ली जाती है, तो हमें कोई कारण नहीं दिखता कि वह प्रतिवादी को कार्रवाई करने के लिए एक सुरक्षित आधार क्यों नहीं दे सका, खासकर जब अपीलकर्ता एक ठेकेदार के रूप में इसकी स्थिति का दुर्व्यवहार कर रहा था जो बड़े पैमाने पर जनता को अनावश्यक उत्पीड़न और उनसे कानूनी रूप से वसूली योग्य न होने वाले धन की वसूली में डाल रही है। एकत्र की गई सामग्री को सक्षम

प्राधिकारी द्वारा अनुबंध की समाप्ति के लिए सही आधार बनाया जा सकता है और बनाया गया है।

20. उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का अन्तिम परिणाम जिसकी हमने पिछले पैराग्राफों में पुष्टि की है, यह है कि अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के अपने असाधारण रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किसी भी राहत का दावा करने का हकदार नहीं था। उच्च न्यायालय, अपीलकर्ता को सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष उचित सिविल कार्रवाई में निवारण की मांग बाबत कर सकता था, चाहे वह नुकसान के लिए हो या प्रतिवादी द्वारा जब्त की गई राशि की वसूली के लिए हो। हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं किया है. इसने अपीलकर्ता को इस हद तक आंशिक राहत दी है कि निष्पादन सुरक्षा और जुर्माने की राशि की जब्ती के कारण बैंक गारंटी का आह्वान उचित नहीं था। किसी भी स्थिति में हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हमारे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है, जो प्रकृति में असाधारण और विवेकाधीन दोनों है। इस संबंध में हम हैल्सबरी के इंग्लैंड के कानूनों के चौथे संस्करण खंड-16 पृष्ठ 874-876 के निम्नलिखित अंश का उल्लेख कर सकते हैं, जो एक ऐसे पक्ष के अधिकार के रूप में इंग्लैंड में कानूनी स्थिति का सार प्रस्तुत करता है जो अदालत में न्यायसंगत राहत का दावा करने के लिए उचित आचरण और

साफ हाथों से से नहीं आया है।

> ''1305. जो समता चाहता है उसे साफ़ हाथों से आना चाहिए। इक्विटी अदालत एक वादी को राहत देने से इनकार कर देती है जिसका मुकदमे की विषय वस्तु के संबंध में आचरण अनुचित रहा है। इसे पहले इस कहावत द्वारा व्यक्त किया गया था "जिसने अधर्म किया है उसके पास समता नहीं होगी", और इस मामले में राहत देने से इनकार कर दिया गया था जहां लेनदेन वादी की धोखाधड़ी या गलत बयानी पर आधारित था, या जहां वादी ने अनुचित तरीके से प्राप्त सुरक्षा को लागू करने की मांग की थी, या जहां उसने विश्वास भंग के लिए एक उपचार का दावा किया जो उसने स्वयं द्वारा किया था और जिससे उसने धन प्राप्त किया था। बाद में यह कहा गया कि इक्विटी में वादी को आचरण के पूर्ण औचित्य के साथ, या साफ हाथों से आना चाहिए। इस सिद्धांत को लागू करने में किसी व्यक्ति को उस संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसे उसने अपने लेनदारों को हराने या कर से बचने के लिए प्राप्त किया है, क्योंकि वह अपने स्वयं के धोखाधड़ी के आधार पर कार्रवाई को बनाए नहीं रख सकता है।

हालाँकि, इस कहावत का मतलब यह नहीं है कि समानता, सामान्य तरीके से भ्रष्टता पर प्रहार करती है; द्वारा चाही गई सूचना को मांगी गई राहत के संबंध में आंका जाना चाहिए, और जिस आचरण की शिकायत की गई है उसका मुकदमा की गई समता से तत्काल और आवश्यक संबंध होना चाहिए; यह कानूनी और नैतिक दृष्टि से भ्रष्टता होनी चाहिए। इस प्रकार, एक नाबालिग की ओर से धोखाधड़ी उसे उसकी स्मतता के बावजूद न्यायसंगत राहत के अधिकार से वंचित कर देती है। जहां लेनदेन स्वयं गैरकानूनी है वहां इस सिद्धांत का सहारा लेना आवश्यक नहीं है। इक्विटी में, कानून की तरह, किसी अवैध लेनदेन के संबंध में आम तौर पर कोई मुकदमा नहीं होता है, लेकिन यह इसकी अवैधता के आधार पर होता है, वादी के अवगुणों के कारण नहीं।''

21. उपरोक्त के आलोक में निर्णय लेते हुए, अपीलकर्ता ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया, निर्दोष नागरिकों को कानून द्वारा निर्धारित राशि से अधिक भुगतान करने के लिए परेशान किया और इस प्रकार न्यायसंगत विचारों पर उच्च न्यायालय का असाधारण रिट क्षेत्राधिकार में हत का दावा करने के लिए अदालत में जाने से पहले खुद को अयोग्य रूप से समृद्ध किया। इस तरह के प्रयास को उच्च न्यायालय द्वारा विफल किया

जाना चाहिए था, जैसा कि वास्तव में किया गया है, चाहे आंशिक रूप से ही क्यों न हो।

22. यह हमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बैंक गारंटी के आह्वान से संबंधित चुनौती के एकमात्र अन्य आधार पर लाता है जो अपीलकर्ता के अनुसार मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मनमाना और अनुचित था। उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि 2,41,097/- रुपये के जुर्माने के अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने निष्पादन सुरक्षा के लिए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत बैंक ड्राफ्ट में से 2,20,00,125/- रुपये की राशि पहले ही वसूल कर ली थी। इस प्रकार, प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कुल राशि अनुबंध के तहत उसे देय राशि से अधिक थी, यदि अनुबंध अवधि के अंत तक इसे परिश्रमपूर्वक निष्पादित किया गया होता। किसी भी अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए बैंक गारंटी का आह्वान करना उच्च न्यायालय द्वारा अनुचित माना गया था।

23. निर्णय के उस भाग के खिलाफ प्राधिकरण द्वारा कोई अपील नहीं की गई है, हालांकि प्राधिकरण की ओर से यह तर्क दिया गया था कि अनुबंध के खंड 18 (बी) के संदर्भ में, प्राधिकरण को अपीलकर्ता-ठेकेदार की ओर से संग्रह की अधिकता का अनुमान लगाने का द्वारा ओर इसकी वसूली का अधिकार था। खंड 18 का इस स्तर पर विस्तार से निष्कर्ष निकाला जा सकता है:

"18. अधिक शुल्क वसूलने पर जुर्माना :

क) यदि यह पाया जाता है और/या प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए स्थापित किया जाता है कि ठेकेदार ने निर्धारित दर से अधिक शुल्क लिया है, तो प्राधिकरण अनुबंध को तुरंत समाप्त कर सकता है और/या रुपये एक लाख या प्राधिकरण द्वारा प्राप्त एक दिन के शुल्क के बराबर राशि, जो भी अधिक हो का जुर्माना लगा सकता है और ठेकेदार को शुल्क संग्रह जारी रखने का एक और अवसर प्रदान कर सकता है। हालाँकि, किसी भी स्थिति में, प्राधिकरण ठेकेदार को एक से अधिक अवसर नहीं देगा।

ख) प्राधिकरण, ठेकेदार द्वारा किए गए शुल्क के अतिरिक्त संग्रह का अनुमान लगाने और उसे वसूलने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है, जो लगाए गए जुर्माने के अतिरिक्त होगा और ठेकेदार से वसूल किया जाएगा।

ग) इस खंड के तहत समाप्ति से ठेकेदार निष्पादन सुरक्षा की बिना शर्त जब्ती के लिए उत्तरदायी हो जाएगा।"

24. उपरोक्त को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि यदि अपीलकर्ता को शुल्क की निर्धारित दर से अधिक शुल्क लेते हुए पाया गया तो प्राधिकरण

अनुबंध को समाप्त करने में सक्षम था। अनुबंध की समाप्ति के अलावा अतिरिक्त शुल्क वसूलने की प्रकृति में किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप धारा 18 (ए) (उपरोक्त) के संदर्भ में जुर्माना लगाया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि खंड 18 (बी) के संदर्भ में अनुबंध की समाप्ति और जुर्माना लगाने के अलावा प्राधिकरण, अपीलकर्ता द्वारा किए गए अतिरिक्त संग्रह का अनुमान लगाने और उससे इसे वसूलने का भी हकदार था। हमारे सामने रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि क्या प्राधिकरण द्वारा ऐसा कोई अनुमान लगाया गया था और यदि हां तो वह किस आधार पर किया गया था। सटीक अनुमान लगाने में प्राधिकरण की विफलता ,बैंक गारंटी के एक साधारण आह्वान द्वारा वसूली के उसके दावे को खतरे में डाल सकती है। यह एक अलग मामला हो सकता था यदि प्राधिकरण ने अतिरिक्त राशि का सटीक अनुमान लगाया होता और बैंक गारंटी का उपयोग करके इसे पुनर्प्राप्त करने की मांग की होती, लेकिन अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त अतिरिक्त राशि के उचित अनुमान के बिना, बैंक गारंटी का वहन करना और उससे कवर की गई पूरी राशि रु. 2,20,00,125/- की वसूली करना प्रतिवादी के लिए खुला नहीं था। उस दृष्टिकोण से, उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि बैंक गारंटी का आह्वान इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं था कि प्राधिकरण ने पहले ही अपने द्वारा लगाया गया जुर्माना वसूल कर लिया था और अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत बैंक ड्राफ्ट के रूप में 2,20 00,125/-रुपये की निष्पादन सुरक्षा राशि भी जब्त कर ली थी।

25. जहां तक अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत बैंक ड्राफ्ट से 2,20,00,125/- रुपये की निष्पादन सुरक्षा की वसूली का सवाल है, हमें यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि ऐसी जब्ती प्रतिवादी-प्राधिकरण के लिए अनुबंध की शर्तों के अधीन उपलब्ध थी। और संविदा अधिनियम कीधारा 74 के प्रावधानों के तहत इस पर रोक नहीं लगाई गई है। धारा 74 का दायरा इस न्यायालय की कई निर्णयों का विषय रहा है, जिसमें फतेह चंद बनाम बालकिशन दासएआईआर 1963 एससी 1405, भारत संघ बनाम राममम आयरन फाउंड्री (1974) 2 एससीसी 231 और सेल बनाम गुप्ता ब्रदर स्टील ट्यूब्स (2009) 10 एससीसी 63 में संविधान पीठ के फैसले शामिल हैं।। इन सभी घोषणाओं में जो सामान्य सूत्र चलता है वह यह है कि एक पीड़ित पक्ष उस पक्ष से मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है जिसने अनुबंध तोड़ा है चाहे वास्तविक क्षति या नुकसान उल्लंघन के कारण हुआ है साबित हुआ हो या नहीं और न्यायालय के पास, निर्धारित दंड की बाहरी सीमा के अधीन, ऐसा मुआवजा देने का क्षेत्राधिकार है जो वह मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित समझे। यह अनिवार्य रूप से कानून और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न होगा जिसे रिट कोर्ट संभवतः तय नहीं कर सकता है। यदि अपीलकर्ता ने संविदात्मक शर्तों के संदर्भ में अपीलकर्ता द्वारा वसूली योग्य राशि की तर्कसंगतता पर सवाल उठाया है, तो उसे उचित सिविल कार्रवाई में अपने उपचार की तलाश करनी चाहिए थी।

26. परिणामस्वरूप यह अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है, लेकिन तथ्यों और परिस्थितियों में, का खर्चों के बारे में कोई आदेश दिए बिना।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजेश चंद्र गुप्ता (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।